प्रेषक,

मनीषा पंवार, प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

ग्राम्य विकास विभाग,

उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2

देहरादून, दिनांकः 14 मार्च, 2018

विषय:— भारत सरकार द्वारा सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017—18 की अनुमोदित योजनाओं हेतु द्वितीय किश्त की केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश अवमुक्त किए जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर सचिव, बी०ए०डी०पी०, ग्राम्य विकास के पत्र संख्याः 190 / 172 / बी०ए०डी०पी० / ए०ए०पी० / एस०पी०एम०यू० / ग्रा०वि० / 2017 दिनांकः 05.02.2018 एवं भारत सरकार के पत्रांकः 1 / 16 / 2017 — BADP दिनांकः 24.01.2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017 — 18 में बी०ए०डी०पी० योजनान्तर्गत अनुमोदित कार्ययोजना की द्वितीय किश्त के रूप में केन्द्रांश की धनराशि शासन के पत्र सं० 277 दिनांक 21.02.2018 के द्वारा धनराशि ₹117.63 लाख निर्गत की गयी है। भारत सरकार द्वारा सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017 — 18 की अनुमोदित योजनाओं हेतु उक्त केन्द्रांश के सापेक्ष 10 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि ₹13.07लाख तथा प्रथम किश्त का शेष राज्यांश ₹20.69 लाख (206.95 लाख — 186.26 लाख), इस प्रकार कुल राज्यांश ₹33.76 लाख (₹तेतीस लाख छियत्तर हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2017 — 18 के आय—व्ययक में प्राविधानित बजट में से स्वीकृत कर आपके निर्वतन पर निम्नांकित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन रखते हुए नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: —

01. योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय एस०एल०एस०सी० द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा, इस सम्बन्ध में अगली किश्त का प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमोदित

कार्ययोजना शासन को प्रस्तुत की जाएगी।

02. प्रत्येक कार्य के आगणन/लागत पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के आदेश सं0 610/XXVII(1)/2017 दिनांकः 30.06.2017 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सनिश्चित किया जाएगा।

03. प्रत्येक कार्य के संबंध में योजना का अनुमोदन सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदान किया जायेगा तथा योजना की अनुमोदित लागत के कार्य को लोक निर्माण विभाग की प्रचलित दरों पर नियमानुसार आगणन गठित कर उनका तकनीकी अनुमोदन सक्षम स्तर से एवं आगणन पर स्वीकृति नियमानुसार प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

स्तर से एवं आगणन पर स्वीकृति नियमानुसार प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

04. स्वीकृत कार्यों पर होने वाले व्यय को वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल उत्तराखण्ड
अधिप्राप्ति / प्रोक्योरमेंट रुल्स, 2017 तथा भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा—निर्देशों,

योजना की गाइड लाइन्स का अनुपालन किया जाय। निर्माण कार्यों पर व्यय करने से पूर्व उसका आगणन गठित कर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

05. प्रश्नगत धनराशि उन्ही कार्यों / प्रयोजनों पर ही व्यय की जायेगी, जिनके लिए स्वीकृत की जा रही है, किसी भी स्थिति में इस धनराशि का व्ययवर्तन नहीं किया जायेगा।

06. किसी भी दशा में इस धनराशि को अग्रिम आहरित कर बैंक में न रखा जाय।

07. प्रत्येक कार्ययोजना के लिये समयबद्धता निर्धारित कर प्रस्तावित योजना का क्रियान्वयन शीघ्रातिशीघ्र चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाए।

08. समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग की प्रचलित दरों व विशिष्टियों के अनुरुप उच्चकोटि गुणवत्ता युक्त सम्पादित किये जायें एवं भूकम्प अवरोधी प्राविधानों को प्राकलनों में समाविष्ट किया जाय।

09. प्रत्येक कार्य के लिये धनावंटन एवं व्यय की सूचना कार्य की उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निर्धारित प्रपत्र पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

10. स्वीकृत की जाँ रही धनराशि का उपयोग दिनांकः 31.03.2018 तक सुनिश्चित किया

जाय ।

11. कार्य पूर्ण होने संबंधी कम्पलीशन प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र संबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त शासन को उपलब्ध कराया जाय।

12. समय—समय पर निर्माण कार्यों में अपेक्षित गुणवत्ता बनाये रखने हेतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रभावी निरीक्षण किया जाए और निरीक्षण की एक प्रति मण्डलायुक्त तथा शासन को उपलब्ध करायी जाय।

13. योजनाओं के क्रियान्वयन में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से

अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. निर्माण की गुणवत्ता के लिये संबंधित कार्यदायी संस्था को अनुबन्ध की शर्तों के अधीन उत्तरदायी बनाया जाय।

15. अनुमोदित योजनाओं को स्वीकृत धनराशि के तहत समय से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

16. योजनान्तर्गत भारत सरकार से धनराशि प्राप्त करने की एवं ससमय व्यय कराने की समस्त जिम्मेदारी नोडल अधिकारी, बी०ए०डी०पी० की होगी।

- 2— इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017—18 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—07 के लेखा शीर्षक 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय—102— सामुदायिक विकास—01—केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं—0101—सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम—42 अन्य व्यय मद में में ₹33.76 लाख की धनराशि (13.07 लाख + 20.69 लाख) (₹तेतीस लाख छियत्तर हजार मात्र) का वहन किया जायेगा तथा उक्त सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या—227 / XXVII-4 / 2017 दिनांक— 13.03.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।
- 4— यह आदेश वित्त विभाग—1 के शासनादेश संख्याः 183/XXVII—1/2012 दिनांकः 28 मार्च, 2012 के अधीन साफ्टवेयर से केन्द्रीय स्तर पर एक विशिष्ट नम्बर S1803070201, S1803070205 दिनांक 14.03.2018 से जेनरेट कर जारी किए जा रहे हैं। संलग्नक यथोपरि।

(मनीषा पंवार) प्रमुख सचिव।

संख्याः /XI/2018/56(96)2009, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1. महालेखाकार, (लेखापरीक्षा), कार्यालय महालेखाकार भवन,कौलागढ़ देहरादून।
- 2. महालेखाकार, (ए.एण्ड.ई.), कार्यालय महालेखाकार भवन,कौलागढ़, देहरादून।
- 3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू०एस०आर०एल०एम० / बी०ए०डी०पी०, ग्राम्य विकास, आजीविका भवन, तपोवन रोड़, देहरादून।
- 4. आयुक्त, कुमाऊं, नैनीताल/आयुक्त, गढ़वाल, पौड़ी।
- 5. जिलाधिकारी, चम्पावत / चमोली / उत्तरकाशी / पिथौरागढ़ / ऊधमसिंहनगर।
- 6. निदेशक, एन0आई०सी०,सचिवालय परिसर।
- 7. अनु सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा० राम बिलास यादव) अपर सचिव।

शासनादेश संख्याः ⁶⁵⁴/XI/18/56(96)2009 े दिनांकः ¹⁹ मार्च, 2018 का संलग्नक

(धनराशि ₹लाख में)

हेतु अवमुक्त ांश के सापेक्ष
ांश के सापेक्ष
ही धनराशि
5.37
0.91
6.28
4.11
6.74
4.37
0.84
0.84
12.79
4.11
4.11
1.00
1.36
33.76

(₹ तेतीस लाख छियत्तर हजार मात्र)

राम बिलास यादव)

अपर सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Rural Development (S041)

आवंटन पत्र संख्या - 65 4 XI/2018/ 56(96)2009 अनुदान संख्या - 007

अलोटमेंट आई डी - S1803070201

आवंटन पत्र दिनांक -14-Mar-2018

HOD Name - Rural Development Commissioner (2252)

1: लेखा शीर्षक

4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव

00 -

102 - सामुदायिक विकास

01 - केन्द्र द्वारा पुरोनधानति योजना

01 - सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम

			Non Plan Voted
मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
42 - अन्य व्यय	231043000	1307000	232350000
	231043000	1307000	232350000

आवंटन पत्र संख्या - 654 XI/2018/ 56(96)2009

अलोटमेंट आई डी - S1803070205

अनुदान संख्या - 007

HOD Name - Rural Development Commissioner (2252)

आवंटन पत्र दिनांक -14-Mar-2018

2: लेखाशीर्षक

4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव

00 -

102 - सामुदायिक विकास

01 - केन्द्र द्वारा पुरोनधानति योजना

01 - सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
42 - अन्य न्यय	230281000	2069000	232350000
	230281000	2069000	232350000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

3376000

